## सत्तराखण्ड शासन राजस्य विमाग संख्याः 9 5 / XVIII(2) / 2010 देहरादृतः दिनांकः // जनवरी, 2010

## अधिसूचना प्रकीर्भ

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904. (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—1 वर्ष 1904) सर्पाठेस उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 230, 294 तथा धारा 344 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में अप्रेत्यर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं.—

# उत्तराखण्ड (अतार प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010

- संक्षित नार क्या 1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश क्रमा। जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2010 है।
  - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- ियम 116-ए व संतर प्रदेश जभींदारी विनाश और भूमि त्यवस्था नियमावली, 1952 का प्रतिस्थापन।
  (उत्तरसंखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 116-ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात-

### स्तम्म-1 विद्यमान नियम

116-ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति धारा 154(4)(3)(क) शासन द्वारा प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा और सम्बन्धित आवेदन कर्ता को यथा स्थिति स्चित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र का समृचित समयायधि में निरतारित न कियं जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। शासन द्वारा दी गयी अनुमति शासनादेश की विधि से 180 दिन तक क्थ एहंगी।

#### स्तम्म-2

एत्दद्वाश प्रतिस्थापित नियम 118-ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क):- शासन द्वारा प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए मूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न वेने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा और सम्बन्धित आवेदन कर्ता को वधास्थिति सूचित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरवायित्व का निर्धारण किया जायेगा। शासन द्वारा दी गयी अनुमति शासनावेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी.

परन्तु यह कि जहाँ ऐसी भूमि का बैनामा अपरिहार्य कारणों से अनुमति की वैधता अवधि में निष्मादित न हो सका हो, वहाँ, शासन, शपधपत्र में उदिलखित ऐसे अपरिहार्य कारणों पर विशिष्ट मामलों पर सम्यक विधारोपरान्त अनुमति की वैधता अवधि को छः छः माह के लिए दो बार तक अर्धात कुल एक वर्ष तक के लिए बढा सकेगा।

नियम ११६-छ का प्रतिपद्मापन। उच्त नियमावली में नीचे स्तम्म-1 में दिये गये विद्यमान नियम 116-उ के स्थान पर स्तम्म-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा: अर्थात-

## स्तम्म-1 विद्यमान नियम

118-ख जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख) कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ पत्र कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा,

### स्तम्म-2

एत्दद्वारा प्रतिस्थापित नियम

118—त जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि

एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय

हेतु अनुमति देना, धारा 164(4)(3)(ख):—

कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस

आशय का रापध पत्र कि क्रय की जाने

वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा

औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया

जायेगा, आवेदन पत्र प्रपत्र—ख के

आवेदन गंत्र प्रपत्र-'ख' के साध जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायंगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जाधेगी। जिला कलेक्टर प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझे उस पर जोंच करायेंगे और प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हए भूमि कय की अनुमति देने अथवा न देने के समान्ध में निजंग लेंगे एवं कारण बताते हुए (speaking arder) आदेश पारित कर समान्धित आयेदक को लिखित अप से सुचित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारण न किये आने पर क्षनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की लिखि से 180 दिन तक वैध रहेगा। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा-154(1) मैं दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रथ की जा सकती है।

साथ जिले के कलेक्टर की प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरना दी जायेगी। जिला कलेक्टर प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझे उस पर जॉच करायेंगे और प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूगि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को लिखिल फप से सुचित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र का सम्चित समयावधि में निस्तारण नं किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में **उत्तरदायित्व** का निर्धापण जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आवेस, ऐसे आवेश की तिथि से 180 विन तक वैश्व रहेगी,

परन्तु यह कि जहाँ ऐसी मूमि का बैनामा अपरिहार्य कारणों से अनुमति की वैधता अवधि में निष्पादित न हो सका वहाँ, शासन, शपधपत्र में हो, उल्लिखित ऐसे अपरिहार्य काश्णों पर विशिष्ट मामलों पए विचारोपरान्त अनुमति की वैधता अवधि को छः छः माह के लिए दो बार तक अर्थात कुल एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकेगा। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रय की जा सकेगी।

> आहाा से (सुभाव कुमार) प्रमुख समिव।

1

sector) in trems

# संख्या 95 XXVIII(II) /2010 एवं तद्दिनाक।

# प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य राजस्य आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमोंक / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्डं।
- 4- महानिबन्धक, निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- गिदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड
- 7— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नियमावली को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 (खण्ड ख) दिनांक-11.1.2010 में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 मुद्रित प्रतिया प्राथमिकता के आधार पर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

श- गार्ड काईल।

White corms

आज्ञा से. द्वितीय बडोनी) अनुसचिव।

1